Demand to provide Rajasthan its share of water from the Ravi River

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि 1981 में रावी-व्यास नदियों के अधिकांश जल के बंटवारे में हुए अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान को 8.60 एम. ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था, लेकिन इस समझौते में यह प्रावधान रखा गया था कि जब तक राजस्थान अपने संपूर्ण हिस्से को उपयोग में लाने की स्थिति में नहीं होगा, तब तक पंजाब राजस्थान के अधिकांश हिस्से के पानी को उपयोग में ला सकेगा। आदरणीय महोदय, बी.बी.एम.बी. में राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ., 52.69 प्रतिशत के बजाय 8 एम.ए.एफ., 49 प्रतिशत हिस्सा मानते हुए जल आवंटित करना शुरू कर दिया। राजस्थान ने अपने हिस्से के 8.60 प्रतिशत पानी के संपूर्ण उपयोग के लिए नहर प्रणाली काफी समय पूर्व ही विकसित कर ली है। लेकिन आज भी राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी आबंटित नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में सूखे की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 8.60 एम. ए.एफ, 52 प्वाइंट 69 प्रतिशत हिस्सा दिलाने की कृपा करें। मैं फिर आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि हमारा राजस्थान इस दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए हमें पानी दिला दीजिए। धन्यवाद।

Need to Modernise Delhi Police in view of increasing crime in Delhi

SHRI JAI PRAKASH AGGARWAL (NCT of Delhi): Sir, I would like to draw the attention of the House to the rising incidence of crimes in Delhi. Unfortunately, in spite of various steps taken by the Delhi Police, many cases of rape have occurred recently, in quick succession, that reflects callousness on the part of the law enforcing agencies, besides, creating a sense of fear and helplessness amongst ordianry citizens, as they receive wide media coverage. Incidents of rapes, robberies, snatchings and terrorism increased substantially in 2005, virtually labelling Delhi as the crime capital of the country. While rape cases increased by more than 18 per cent, the city witnessed an increase of 11.71 per cent in burglaries, 10.43 per cent increase in robberies, and an astounding 47.48 per cent increase in cases of snatchings in the year 2005. However, cases of dacoity, murder, and attempt to murder have decreased by 10.34 per cent, 2.89 per cent and 11.46 per cent respectively. There are numerous instances wherein perpetrators of crime against women and older persons who are residing alone have been able to get

away with the crime due to lack of timely intervention by the police. Sir, therefore, there is an urgent need to modernize and equip the Delhi Police. All the police stations in Delhi should not only be computerized but also be linked by a local area network and a wide area network. 'The global positioing system' should be immediately introduced to track movement of PCR vans in a bid to reduce reaction time for distress calls. Thank you, Sir.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I associate myself with his Special Mention.

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विशेष उल्लेख से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[شری شاہد صدیقی "اترپردیش" : میں مانئے سدسے دوارا اٹھائے گئے ویشیش الیکھ سے اپنے کو سمبدھ کرتا ہوں۔]

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश): मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विशेष उल्लेख से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

Concern over problems in giving Honorary Pension to Freedom Fighters

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति महोदय, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन शुरू करते समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अपेक्षा थी कि स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाए और इस समय अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गरीबी तथा बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिले। किन्तु नौकरशाही के ढीलेपन के कारण सरकार अपने लक्ष्य को ही नहीं पा सकी है। आज भी बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन पाने के लिए भटक रहे हैं। सरकारी तंत्र द्वारा उनके आवेदनों पर अनावश्यक अडंगे लगा दिए जाते हैं, जबकि वे अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जिन्हें राज्य सरकारें सम्मान निधि दे रही हैं, उनके प्रकरण भी केन्द्र सरकार के समक्ष अनिश्चित पड़े हैं। हैदराबाद आन्दोलन से जुड़े श्री एम. कुमारेल्ली वारंगल सहित 300 स्वतंत्रता सेनानी 6 माह पूर्व दिल्ली आए थे और उन्होंने आवेदन दिया था, किन्तु आज तक उन पर निर्णय नहीं हो सका है। तेलंगाना के 61 लोगों को सम्मान निधि प्रदान करने का मामला जून 2004 से अभी तक हल नहीं हो सका है। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे लम्बित पड़े

†[] Transliteration in Urdu Script.